श्री राम नाईक: इस पैकेज के अनुसार पेट्रालियम मंत्रालय ने काम किया है। असम और नॉर्थ-ईस्ट के क्षेत्रों में भी शोध कार्य हम तीव्र गति से कर रहे हैं। इन्होंने डिस्ट्रिब्यूशन की जो बात कही, राजस्थान के बारे में मैंने कहा था कि वहां हम कुछ अधिक पैट्रोल पम्प बना रहे हैं। ठीक यही व्यवस्था हम नॉर्थ-ईस्ट के लिए भी कर रहे हैं। इससे पहले नॉर्थ-ईस्ट में सेपरेट डीलर सिलेक्शन बोर्ड नहीं था। हमने नॉर्थ-ईस्ट में सेपरेट सिलेक्शन बोर्ड बनाया है जिससे वहां के फैसले अन्य राज्यों से पहले होंगे और इसका लाभ नॉर्थ-ईस्ट राज्यों को मिलेगा।

*386. *[The Questioner (Shri Brahmakumar Bhatt) was absent, for answer vide page 29 infra]*

*387. *[The Questioner (Shri Sukhdev Singh Libra) was absent, for answer vide page 29 infra.]*

Impact of globalisation

*388. SHRI SWARAJ KAUSHAL: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the impact of globalisation on the domestic industry, agriculture and employment in the country; and

(b) what is the basis of Government's findings and conclusions in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DR. RAMAN): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The impact of globalization on domestic industry, agriculture and employment in the country has been analyzed in various issues of Economic Survey, Plan Documents of Planning Commission and other reports of the Government. The summary conclusions which emerge from these reports reveal the following:

* Globalization and economic liberalization has enhanced competition, increased economic efficiency and augmented productivity of the domestic industry. As a result the industrial sector which recorded an average annual compound growth rate of 4.6% from 1970-71 to 1979-80 and 6.6% from 1980-1981 to 1989-90 achieved a high growth rate of 7.3% in Eighth Plan (1992—97).

In the pre-reform period the agricultural sector had grown at the rate of 3.16 per annum from 1981-82 to 1985-86 and at the rate of 3.59% per annum from 1985-86 to 1989-90. In the post reform period however, the agricultural sector has registered a higher growth rate of about 3.9% during the Eighth plan period (1992-97).

The average annual growth rate of overall employment (both organized or unorganized sectors) after continuously declining from 2.75% in the period 1972—78 to 1.77% in 1983—1988, but increased to 2.37% in the period 1987—1994.

Thus the broad trends of growth in the post reform period indicate that the impact of globalization on domestic industry, agriculture and employment have been by and large positive.

श्री स्वराज कौशल: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे करीब चौदह आइटम्स हैं जिनके भारत से एक्सपोर्ट पर यूरोपियन यूनियन ने एंटी डम्पिंग और एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगाई है तथा पांच उद्योग या प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिन पर प्रोविजनल ड्यूटी लगाई है। जब यह कम्प्लेंट भारतीय उद्योग से प्राप्त हुई तो भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप अपनी रिपोर्ट कब तक देगा और इस संबंध में कब तक ठोस कदम उठाएगा? जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक सरकार इन उद्योगों को राहत देने के लिए क्या कर रही है?

डा. रमण: सभापति जी, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी तथा एंटी डम्पिंग ड्यूटी के जो प्रभाव हो रहे हैं उस पर सरकार क्या कार्रवाही करने जा रही है, सभापति जी, यह विषय, जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट और उस रिपोर्ट की सारी जानकारी कलेक्ट करने तथा उसका अध्ययन करने से संबंधित है। कमेटी की रिपोर्ट की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है लेकिन अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगी। परंतु आज की तारीख में यह बताना कठिन है कि रिपोर्ट कब तक आएगी लेकिन हमारी कोशिश है कि रिपोर्ट शीघ्र ही आ जाए। जिस विषय पर सदस्य चर्चा कराना चाहते हैं उसका अध्ययन हो रहा है और अध्ययन करने के बाद उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी।

श्री स्वराज कौशल: मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी आनरेबल मिनिस्टर से यह है कि क्या गवर्नमेंट के नालेज में यह है कि सीमेंट इंडस्ट्री बड़ी दुर्दशा में है और बहुत सारी सीमेंट यूनिट्स हैं, यहां तक की टाटा एसीसी की अपनी यूनिट्स को बेच रहा है। मैं जानना आहता हूं कि ऐसी कितनी सीमेंट फैक्टरीज हैं जिन्हें भारतीय कंपनियों ने विदेशियों को बेच दिया है और सरकार इसके बारे में क्या स्टेप ले रही है?

डा. रमण: माननीय सदस्य ने सीमेंट कंपनियों की हालत के संबंध में जो चिंता प्रकट करते हुए पूछा कि हमारी सीमेंट कंपनियों को बाहर की कंपनियां खरीद रही हैं। इसके बारे में मुझे कहना है कि जो डिमांड रहती है, खासतौर से सीमेंट इंडस्ट्री ऐसी है जो लोकल डिमांड के आधार पर उसका प्रोडक्शन कम और ज्यादा करती है। इस में पिछले दो तीन सालों में स्थिति में कुछ सुधार आया है। जहां तक माननीय सदस्य उन कंपनियों का नाम जानना चाहते हैं जिनको बाहर की कंपनियों, मल्टीनेशनल कंपनियों से खरीदा है तो मैं सारी जानकारी सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति जी, सारी बात सामने आनी चाहिए। मंत्री जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है कि रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, कितने उद्योग बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं। इसकी जानकारी सदन के सामने आनी चाहिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: क्वेश्चन का उत्तर आ गया है और सही जवाब आया है।

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, we have been given to understand that the Government has removed quantitative restrictions on 714 items. We were forced to remove the QRs because India lost the case in the WTO when some of the developed countries raised the question that the balance of payments position of India has improved. India disputed this in the WTO Council, saying that it was not so. But, when the Indian advocates were confronted with the information that the Finance Minister and other Ministers day in and day out had made out the case that our balance of payments position had improved, we lost the case, and we had to open up.

Simultaneously, we are also given to understand that some of the developed countries did not go in for any *quid pro quo* in areas where India had a comparative advantage, like the multi-fibre agreement, which was to be phased out but only 4 per cent integration had taken place. Therefore, in the light of this, with the hon. Minister say whether our Government's response to the Challenge of globalisation has been adequate or not?

डा. रमण: माननीय सदस्य की प्रमुख चिंता 714 आइटम क्यूआरएस में खोलने के बारे में है। भारत की आर्थिक स्थिति, उसका प्रभाव इसके बारे में माननीय सभापति जी, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 1992 के बाद जब से आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई है तब से निरन्तर आर्थिक रोजगार-सृजन उद्योगों का उत्तरोत्तर विकास हुआ है।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, that is not my question. I seek your protection. He is just repeating what he has given in the written statement.

डा. रमण: 714 आइटम को क्यूआरएस में लाने के बाद की पोजीशन के बारे में माननीय सदस्य चिंता कर रहे हैं कि इससे हिन्दुस्तान के हमारे उद्योगों पर क्या असर पड़ा है। सभापति महोदय, इस विषय को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सेफ गार्ड्स हैं--

श्री नीलोत्पल बसु: यह मेरा सवाल नहीं था। Sir, please protect me.

MR CHAIRMAN: Mr. Minister, he is asking a different question. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I have not asked about the impact. I asked whether India's response was adequate or not.

SHRI T.N. CHATURVEDI: Yes, it was adequate.

SHRI NILOTPAL BASU: It was not adequate. How can it be adequate? They have only quoted our sources. They have quoted the statements of our Ministers to prove their case. How can it be adequate?

SHRI T.N. CHATURVEDI: Those figures are always available ...*(Interruptions)*...

VEN'BLE DHAMMAVIRIYO: Let the Minister reply. ...*(Interruptions)*...

SHRI T.N. CHATURVEDI: I can always supplement it. I am only supplementing it. It is not necessary that only the Minister should reply. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: I will be more than happy. Let him answer.

डा. रमण: माननीय सभापति महोदय, एक ही कारण यह है कि हिन्दुस्तान में जो क्रॉप की स्थिति है और पेट्रोलियम पूल में जो शार्टेज हुई है, जो कीमतें बढ़ी हैं, इन सारे विषय पर जो आज हमारी आर्थिक स्थिति है, इस पर माननीय सदस्य चिंता कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। सारे विषयों पर सरकार चिंता कर रही है। इस पर हमने सोचा है। इस विषय को पूरी गम्भीरता के साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी के सामने हमने अपना पक्ष रखा। अपना पक्ष पूरी ताकत के साथ हिन्दुस्तान और हमारा विभाग रखने जा रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी कि हम अपना पक्ष मजबूती के साथ वहां न रख सकें और भारत किसी विषय में ऐसा समझौता नहीं करेगा जिससे हमारे आर्थिक और यहां के भारतीय पक्ष का नुक्सान हो।

SHRI EDUARDO FALERIO: Sir, I am astounded at the reply of the hon. Minister, when he says that the impact of globalisation has been positive; Full-stop. There is no developing country in the world, including those countries that have benefited the most from globalisation, like China and the so-called Asian Tigers, which says so. They don't say this. At the most they say that it is a mixed result, as far as the developing countries are concerned. As far as India is concerned, it is also the same reaction. I want to specifically ask the hon. Minister whether his attention has been drawn to a manazine, *Swadeshi,* which is published by a Member of this House, who belongs to the ruling party, Mr.

Mahesh Chandra Sharma. The magazine is highly critical of flobalisation. It has been commented upon today in *The Hindu,* and sometime back, the *The Hindustan Times.* The magazine is published from the residence of the Union Minister, Mr. Anantha Kumar.

डा. रमण: सभापति महोदय, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग प्रभाव दिखाई दिये हैं मगर सभी क्षत्रों में ऐसा है, पूरे उद्योग विभाग में ऐसा है, कहना ठीक नहीं है। सीमेंट अलग विषय है। चाइना बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरे देश भी कर रहे हैं। हिन्दुस्तान की जो परिस्थिति है और यहां जो इनफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो एफ.डी.आई. आ रहा है, उस विषय में जो माननीय सदस्य की चिंता है, हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम को भी लाभ मिले। (**व्यवधान**)

श्री टी.एन. चतुर्वेदी: यह स्वदेशी का अलग-अलग दृष्टिकोण है। (**व्यवधान**)

SHRI EDUARDO FALERIO: I would like to know whether his attention has been drawn to the comments published in the magazine. If so, what is his reaction to it?

डा. रमण: सभापति महोदय, स्वदेशी के आन्दोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वह चिंता कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिलाया है। माननीय सभापति महोदय, यह चिंता स्वदेशी आन्दोलन से जुड़े हुए लागों की हो सकती है मगर सरकार इसके उपर नज़र रखे हुए है और स्वदेशी इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री को कोई नुक्सान न हो, सरकार इसके लिए चिंतित है।

श्री संजय निरुपम: आदरणीय सभापति महोदय, उदारीकरण और वैश्वीकरण हुआ है, उसका निश्चित तौर पर घरेलू उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। माननीय मंत्री महोदय अपने आप को सूट करने के लिए जो भी आंकड़े देना चाहें, दे लें, पूरा देश इससे सहमत नहीं है। अभी बहुत सारी ऐसी छोटी कंज्यूकर प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे देश के उत्पादक उत्पादन करते थे। कृषि से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें थी जैसे सेब है, जिसका अच्छा खासा यहां उत्पादन हो रहा है और इससे हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के किसानों की रोजी रोटी चलती रही है। अचानक आपने सेब को ओपन कर दिया और न्युज़ीलैंड से बड़े पैमाने पर आज कल सेब आ रहा है और वह सेब सस्ता पड़ने लगा है। हमारे देश के सेब उत्पादक परेशान हैं। इसी प्रकार से अंडे भी बाहर से आने लगे हैं। हमारे यहां गरीब और साधारण लोग अंडों के उत्पादक थे, जो अंडे के उत्पादक थे, उनसे भी सस्ता अंडा आजकल बाहर से आने लगा है। तो एक विचार हमेशा रहा है कि यह जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इनका एक फ्लोर प्राइस तय कर दिया जाए, एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया जाए ताकि हमारे उत्पादकों को सूट कर सके, हमारे उत्पादक उस कंपेटीशन को फेस कर सकें। तो ऐसा फ्लोर प्राइस आज तक निर्धारित नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं, छोटे छोटे सामानों के जो उत्पादक हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या इस तरह के कंज्युमर प्रोडक्ट्स के फ्लोर प्राइस निर्धारित करने की दिशा में कोई निर्णय लेगी?

डा॰ रमण: इसमें कोई फिक्स फ्लोर प्राइस निश्चित करने की बात नहीं है। जहां तक चिंता यह है कि एपल और अन्य क्षेत्रों में जो हिंदुस्तान के हमारे बाजार को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि एपल जो आया है वह टोटल जो हमारे यहां पर रिक्वायरमेंट है उसका 2 प्रतिशत से ज्यादा नहीं आया है और कोई बहुत डम्पिंग उसके लिए नहीं हुई है। जो प्राइस तय होता है वह उस समय के मार्केट के हिसाब से निर्धारित रहता है। जहां तक छोटे व स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिए और जो अन्य सेक्टर हैं उनके लिए जो उपयोगी सामान हैं उन समानों के ऊपर जो चिंता की कि इनका रेट....(व्यवधान) उसके लिए जो छोटे आइटम हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में प्राइस होते हैं उनके बारे में सरकार चिंता कर रही हैं माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह बहुत उपयोगी है और सरकार उस बिंदु पर विचार करेगी।

SHRI PREM CHAND GUPTA: Mr. Chairman, Sir,.....*(Interruptions)*....the steel and cement industry is an important indicator to the industrial and the economic health of a nation. The Minister, in his reply, has stated that the impact of globalisation on the domestic industry, agriculture and employment has, by and large, been positive. Mr. Chairman, Sir, not only these two important segments of the industry are in a bad shape, but the general condition of the industry is also going from bad to worse. The impact of globalisation and the open import has been felt during the years 1997, 1998 and 1999. But the Government has not given any statistics of these periods. I would like to ask the Minsiter, what is the impact of globalisation during these three years, 1997 to 2000?

Secondly, on what basis they say that the impact of globalisation has been positive?

डा॰ रमण: वर्ष 1997 से लेकर 2000 तक कृषि और उद्योग खास तौर से उद्योग की चिंता माननीय सदस्य कर रहे हैं। जो पुराने हमारे 1992 से 1997 और 1997 से 2000 के बीच के आंकड़े देखें तो आज जो हमारे औद्योगिक विकास की दर है वह 6.2 है और हमने तय किया था या नवीं पंचवर्षीय योजना तक हमारा जो लक्ष्य था वह 8.2 का था। माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूंगा कि जो 6.2 की जो ग्रोथ है, विकास की दर है इस विकास दर का आने वाले तीन महीनों में जो रेट है हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि 8.2 तक पहुंचेगा। तो उद्योग के बारे में पूरा जो इस क्षेत्र में प्रभाव पड़ने वाला है उसका असर ठीक होगा और संभावना है कि 8.2 प्रति वर्ष की दर से विकास दर का जो लक्ष्य हमने रखा है 2001-2002 तक, यह बढ़ने की संभावना है। आज 1997-2000 में 6.2 की विकास दर है...(व्यवधान)

श्री सभापति: बस हो गया, श्री वेंकैया नायडू।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Chairman, Sir, I would like to confine myself to this particular part of agriculture because of the QRs being removed on 714 items. The impact on agricultural production is being felt by the farmers, by the people. The industry has the capacity to withstand world competition. But now, in this transitory period, the effect on agricultural produce is being felt by the farmers because there is a competition; and the foods that are beign imported are cheaper than the products that are produced here. That being the case, we have a mechanism to resort to anti-dumping measures. Is it the stand of the Government that unless the individuals make a representation—and then the Department takes particular time to study it—they would not resort to this? Will the Government keep this in view, the wider national interests, particularly, of the agricultural community who are not organized? You cannot expect each one of them to come and file a representation before the concerned authorities, saying, "Please protect us?" Sir, you know that industries, at least, have the needed infrastructure, they have the capacity to come and reach. Will the Government of India, particularly, the Commerce Ministry, in consultation with the Agriculture Ministry, take steps to see that steps are initiated, watching the market from time to time, to see that anti-dumping measures are resorted to with regard to agricultural produce import?

डा० रमण: माननीय सभापति जी, 714 आइटम्ज़ पर क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन हटने के बाद, खास तौर पर कृषि पर आधारित जो क्षेत्र है, उस पर चिंता की गई हमने इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी और अन्य टैक्स बढ़ाये। जैसे चावल पर जीरो से हंडरेड परसेंट कर दिया, मिल्क पर टैक्स बढ़ाया और अन्य जो कृषि आइटम्ज़ हैं, जैसे मक्का पर बढ़ाया, एडिबल आयल और पॉम आयल पर 35 से 40 परसेंट किया है। इन सभी विषयों पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका असर हमारे किसानों पर न पड़े और कृषि पर आधारित जो किसान हैं उन पर इसका प्रभाव न पड़े। एंटी डंपिंग ड्यूटी के साथ-साथ अन्य जो टैक्स हैं उन्हें हम हंडरेड परसेंट करना चाह रहे हैं और वित्त मंत्री जी के साथ तथा अन्य मंत्रालयों के साथ मिल कर यह चिंता की जा रही है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे किसानों को कम से कम नुकसान हो और इसके लिए अध्ययन किया जा रहा है। अभी कुछ आइटम्ज़ पर जिनकी अभी माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, हमने चावल से लेकर मक्का और दूध व अन्य जो आइटम्ज हैं, उन पर हमने एंटी डंपिंग के साथ-साथ जीरो से हांडरेड परसेंट टैक्स किया है।

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर: आनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो स्माल स्केल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में एम्प्लायमेंट के बारे में जवाब पाज़िटिव में दिया है और बाद में अपने आंसर में इन्होंने कहा है कि चिंता भी है, तो मैं इनसे

यह बात जानना चाहता हूं कि वह चिंता तो कर रहे हैं लेकिन हिन्दुस्तान की इंडस्ट्री में हरियाणा में आप अंबाला देख लीजिए, पंजाब में लुधियाना और जलंधर वहां 25 परसेंट स्माल स्केल इंडस्ट्र तकरीबन बंद हो गई है और अनएम्प्लायमेंट लाखों में चली गई है। एग्रीकल्चरल में आयल सीड में किसान फेल हो गया, व्हीट और राइस पंजाब के गोदामों में भरा पड़ा है और उसको कोई उठा नहीं रहा है। यह सब देश में बाहर से आ रहा है। पाल्ट्री और डेयरी में पंजाब और हरियाणा तबाह हो गया है। अब जब किसान तबाह हो गया है तो उसके बाद आप यह चिंता कर रहे हैं। इसलिए चिंता तो आप कर रहे हैं, इंपैक्ट पाज़िटिव बता रहे हैं ताकि आगे के लिए समूचा ही देश बर्बाद न हो जाए, अन-एम्पलायमेंट करोड़ों में न चली जाए। तो जल्दी से जल्दी आप क्या उपाय कर रहे हैं कि सब जो डयूटी है, आयल सीड है, टी वाला है, मिल्क वाला है, पोल्ट्री वाला है और व्हीट वगैरह जो भी है, वहां 100 परसेंट के करीब डयूटी लगायेंगे ताकि आगे दो-तीन साल के लिए कंट्री में इंपोर्ट न हो, और यहां का किसान और स्माल स्केल इंडस्ट्री-वाला अपने पांव पर खड़ा हो सके? अन्यथा अब तो बर्बादी की तरफ चला ही गया है। फिगर्ज़ कुछ और बताती हैं और सही पोज़ीयान देश की कुछ और ही है, यह आप हाउस में किसी से भी पूछ लीजिए, यही मैं जानना चाहता हूं?

डा॰ रमण: महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है देश की स्माल स्केल इंडस्ट्री के बारे में और साथ ही एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो विषय हैं उनके बारे में, जिसका उनको लगता है कि क्यू॰आरज़ हटने के बाद हमारे क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है, तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने इस विषय पर काफी चिंता की है और टैक्स के विषय में जो इन्होंने कहा है कि...(**व्यवधान**)

आयल के ऊपर, माननीय सभापति महोदय, आयल के ऊपर 25 परसेंट से 45 परसेंट टैक्स पहुंचा है, चावल के ऊपर बढ़ाया है, मिल्क के ऊपर बढ़ाया है, मक्के के ऊपर बढ़ाया है। ये सारे उपाय सरकार कर रही है। सरकार को इस बात की भी चिंता है कि हमारे किसानों के ऊपर इसका प्रभाव न पड़े। जहां तक स्माल सकेल इंडस्ट्री का सवाल है...(**व्यवधान**) इंडस्ट्री के बंद होने के अन्य कारण हैं। पॉवर की कमी है, हमारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसे जब तक विकसित नहीं किया जाएगा या छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जिनकी हालत आज ठीक नहीं है, जैसे माननीय सदसय बता रहे हैं और दूसरी जो चिंता है कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि पर आधारित किसानों के हित का जो विषय है, इस पर भी मैंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है और आने वाले समय में, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों के हित में सरकार और भी कदम उठायेगी तथा साथ ही साथ, हमारे उद्योगों और कृषि को नुकसान न होने दें, इसकी भी हमें चिंता है।...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.